एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस
वार्षिक व्याख्यान 2014

"बदलते वैश्विक समीकरण: क्या भारत इनका लाभ उठा पाएगा?"
विषय पर प्रो. किशोर महबुबानी का व्याख्यान

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

वाई. बी. चव्हाण केन्द्र, मुम्बई– 400021 में
शुक्रवार, 14 फरवरी, 2014 को
आयोजित यह 29वाँ एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस
वार्षिक व्याख्यान है।

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

इस व्याख्यान का कोई भी अंश भारतीय निर्यात–आयात बैंक की पूर्वानुमति के बिना पुनर्प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इस व्याख्यान में व्यक्त किए गए विचार और निर्वचक लेखक के हैं और वे भारतीय निर्यात–आयात बैंक पर आरोप्य नहीं हैं।

'' बदलते वैश्विक समीकरण: क्या भारत इनका लाभ उठा पाएगा?''

प्रो. किशोर महबुबानी

देवियों और सज्जनों,

आज की शाम आप सबको संबोधित करना मेरे लिए गर्व की बात है। सबसे पहले तो मैं आप सबको यह स्पष्ट कर दूँ कि इस व्याख्यान के लिए इससे पूर्व पधारे अन्य वक्ताओं की तरह मैं कोई प्रोफेशनल अर्थशास्त्री नहीं हूँ। मेरी विशेषज्ञता केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों और जियोपॉलिटिक्स में है और यह दोनों ही विषय जितना व्यापार (ट्रेड) तथा इकोनॉमिक्स से प्रभावित है उतना ही व्यापार और अर्थशास्त्र इनसे।

अत: आज मैं आपसे इसी जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक दशाओं के बीच के संबंधों पर चर्चा करूँगा जिनके चलते एक नई संकल्पना 'ग्रेट कनवर्जेंस' का उदय हुआ जिस पर मैंने हाल में ही एक पुस्तक भी लिखी है। मैं इस ग्रेट कनवर्जेंस युग में भारत की स्थिति पर चर्चा करूँगा। आज का मेरा व्याख्यान तीन खंडों में बँटा होगा। पहले मैं इस ग्रेट कनवर्जेंस के बारे में संक्षेप में बात करूँगा और फिर बाद में मैं यह बताने का प्रयास करूँगा कि मेरी नजर में यह अभी क्यों घट रहा है और अंत में मैं इस ग्रेट कनवर्जेंस के समय भारत के लिए विद्यमान अवसरों पर बात करूँगा।

मेरी पुस्तक 'ग्रेट कनवर्जेंस' विश्व में विद्यमान वर्तमान निराशावादिता के विपरीत आशावादिता पर केन्द्रित है। मेरा यह मानना है कि मानव विकास के इतिहास का यह स्वर्णिम युग है, यहाँ तक कि पिछले कुछ दशकों की तुलना में भी यह काफी बेहतरीन युग है। हालांकि मेरी इस मान्यता को लेकर कई विवाद हुए हैं, पर आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। आइए देखें किस प्रकार? मानव इतिहास के किसी भी काल

खंड की तुलना में आज देशों के बीच युद्ध में कम से कम व्यक्ति मर रहे हैं। 1950 के दशक में प्रतिवर्ष औसतन 6 युद्ध हुए हैं। नई सहस्राब्दि के पहले दशक में यह औसत घटकर मात्र 1 पर आ गया है। शीत युद्ध के उपरान्त हर संघर्ष के दौरान प्रति युद्ध मृतकों की संख्या 76 प्रतिशत रही है जो शीत युद्ध के दौरान दर्ज प्रतिशत से कम है। यदि हम आंतरिक सशस्त्र संघर्षों की बात करें, तो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओस्लो के अनुसार गृह युद्ध में संलिप्त देशों की संख्या 2009 के 15 प्रतिशत से घटकर 2050 में 7 प्रतिशत रह जाएगी। यदि आप इसे और विस्तार में जानने के इच्छुक हैं तो स्टीवन पिंकर्स की पुस्तक 'दि बेटर ऐंजिल्स ऑफ़ अवर नेचर' पढ़ें जो विश्व के इतिहास में हिंसा की समग्र गिरावट पर शोध परक उदाहरणों के माध्यम से प्रकाश डालती है।

इसी प्रकार विश्व में समग्र गरीबी (एब्सोल्यूट पॉवर्टी) भी घट रही है। वैश्विक गरीबी को घटाकर आधा करना, हमारे कुछ सहस्राब्दि लक्ष्यों में से एक है; और जिसे समय पर प्राप्त कर लिए जाने की पूरी उम्मीद है। वैसे यदि सच कहें तो इसे निर्धारित अवधि से 5 साल पहले अर्थात् 2010 में ही प्राप्त किया जा चुका है। अमेरिका की राष्ट्रीय बौद्धिक परिषद के अनुमानों के अनुसार 2030 तक विश्व से गरीबी लगभग समाप्त हो जाएगी। गरीबी में कमी के इस अभूतपूर्व बदलाव के कई दूरगामी परिणाम हुए हैं– वैश्विक शिशु मृत्यु दर जो 1990 में 63 प्रति हजार थी घटकर 2012 में 35 प्रति हजार रह गई है। दुर्भाग्यवश इस मामले में भारत विश्व रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर सका है। भारत में गरीबी दर 2010 तक घटकर 36.3 प्रतिशत रही है, क्योंकि भारत में गरीबी दूर करने संबंधी विश्व बैंक की परियोजनाएं कुछ वर्ष देरी से शुरू हो सकीं। भारत की शिशु मृत्यु दर भी 43.8 प्रति हजार है जो वैश्विक आंकड़ों से अधिक है।

अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि इस व्याख्यान की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण आंकड़े हैं– 2010 में विश्व स्तर पर मध्यवर्गीय जनसंख्या 850 मिलियन थी, आगामी 2020 तक यह संख्या 3.2 बिलियन तथा 2030 तक 4.9 बिलियन के स्तर पर पहुँच जाएगी। केवल एशिया में ही मध्यवर्गीय जनसंख्या 2010 के 500 मिलियन से बढ़कर 2020 में 1.75 बिलियन हो

जाने का अनुमान है, जो वैश्विक वृद्धि का 85 प्रतिशत होगी। 2020 में विश्व की आधी मध्यवर्गीय जनसंख्या एशिया से होगी तथा 2030 तक यह लगभग दो तिहाई के स्तर पर पहुँच जाएगी। यह विकास मानव इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है, जिसका पूरे विश्व पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा।

हालांकि फिर से भारत में यह परिवर्तन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। 2010 तक भारत की मध्यवर्गीय जनसंख्या 69.17 मिलियन स्तर पर थी अर्थात् कुल जनसंख्या के मात्र 6 प्रतिशत से भी कम; इसके विपरीत चीन की वर्तमान मध्यवर्गीय जनसंख्या 300 मिलियन है जो कि अमेरिका की पूरी जनसंख्या के बराबर है।

यह रूझान पश्चिम और शेष विश्व के बीच अंतर को तेजी से कम कर रहे हैं और सैम्युअल हटिंग्टन की संकल्पना ''ग्रेट डाइवर्जेंस'' के विपरीत हैं जब एशियाई देश औद्योगिक क्रांति[1] के मामले में पश्चिम से पीछे थे। यह ग्रेट कनवर्जेंस न केवल भौतिक समृद्धि के मामले में रहा है बल्कि हमारे मूल्यों और हमारी आकांक्षाओं के मामले में भी घटित हो रहा है। पूरे विश्व में आज लोग लगभग एक ही तरह की अपेक्षाएं रखते हैं– मध्यवर्गीय या उससे उच्च जीवन स्तर तक पहुँचने की – ताकि वे अपने बच्चों को ढंग से शिक्षित कर सकें और हिंसा मुक्त समाज में बिना किसी भय के जीवन व्यतीत कर सकें। इसने विभिन्न संस्कृतियों और यहाँ तक सभ्यताओं के लोगों में बेहतर समझ विकसित की है। यह ग्रेट कनवर्जेंस इसी बदलाव को रेखांकित करता है। मैंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि मानवता एकजुट हो रही है और इसे मैं ''मानकों का आम सहमति से एक रूप होना'' की प्रक्रिया कहना चाहूँगा और यह मानक हैं– आधुनिक विज्ञान, तर्क, मुक्त अर्थव्यवस्थाएँ, सामाजिक समझौते और बहुपक्षवाद।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत ने आधुनिक विज्ञान के मामले में बहुत तरक्की की है। 1987 से 2009 की अवधि के दौरान भारतीय छात्रों ने विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में अकेले अमेरिका में ही 24,800 डिग्रियाँ हासिल कीं जो कि विदेशी छात्रों को प्रदान की गई डिग्री की दूसरी सबसे बड़ी

[1] सरजू रथ, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन प्री मॉडर्न इंडिया एंड दि ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ नॉलेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज न्यूज लेटर (2008)–http://www.iias.nl/sites/default/files/IIAS NL56 32.pdf.

संख्या है। भारत में हर वर्ष 6,90,000 विज्ञान व गणित के छात्र निकलते हैं और इस प्रकार प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले विज्ञान व इंजीनियरिंग छात्रों की दृष्टि से भारत ने अमेरिका, जापान तथा चीन को पीछे छोड़ दिया है। प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।

स्टीवन पिंकर्स की पुस्तक 'दि बेटर एंजिल्स ऑफ़ अवर नेचर', जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, में यह बताया गया है कि 'गरीबी में कमी' एक ऐसा त्वरित प्रभाव है जो मानव समुदाय को न केवल हिंसा से बचने की योग्यता बल्कि दूसरे देशों और संस्कृतियों के लोगों के साथ समानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने को प्रेरित करता है। पिंकर इसे 'स्केलेटर ऑफ़ रीज़न' की संज्ञा देते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब ने इसमें अभूतपूर्व योगदान दिया है। 2010 में जब चिली के खान मजदूर 69 दिनों तक खान में फँसे रह गए थे उस समय लगभग 1 बिलियन लोगों ने इस बचाव अभियान को अपने टीवी सेटों और इंटरनेट पर देखा। पूरे विश्व में अमेरिकी स्टाइल के एम.बी.ए. लोगों ने जब कारोबारी जगत और नीति निर्माण के क्षेत्र में आना शुरू किया तो उन्होंने वैश्विक स्तर पर संभ्रान्त वर्ग को एक समान भाषा और मूल्य दिए। हमारी अंतर निर्भरता और जुड़ाव किस प्रकार संघर्ष को रोक सकते हैं। यह हम अभी भारत-चीन सीमा विवाद के समय देख चुके हैं। हालांकि दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त था किन्तु दोनों देशों के नेताओं ने बेहद संजीदगी और व्यावहारिकता का परिचय देते हुए तनाव को समाप्त किया। इसका कारण यही है कि भारत-चीन के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति में बहुत कुछ दांव पर लग सकता था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2013 में 65.4 बिलियन यू ए डॉलर का है और लगातार बढ़ रहा है तथा कई मुद्दों पर दोनों देशों के साझा हित हैं जैसे अफगानिस्तान में शांति बहाली, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन आदि।

तीसरा मानदंड है-मुक्त अर्थव्यवस्था। शीत युद्ध की समाप्ति ने एक ऐसे युग का अंत देखा जहाँ नियोजित अर्थव्यवस्थाओं पर मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्थाओं को विजय हासिल हुई। अब उत्तर कोरिया को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो यह न मानता हो कि मुक्त अर्थव्यवस्थाएँ वृद्धि और

विकास को प्रोत्साहित करती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को भी 1991 में नरसिंहाराव जी की सरकार द्वारा आर्थिक संकट के बाद लाए गए उदारीकरण/सुधारों का जबरदस्त लाभ मिला। इससे 1992 में प्रति व्यक्ति जी डी पी में 12.8 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई। चीन, जहाँ डेंग जियोपिंग के नेतृत्व में सुधारों पर बहुत पहले कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, में प्रति व्यक्ति जी डी पी 1960 से 1978 के बीच के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 1979 से 1998 की अवधि के बीच 9.4 प्रतिशत हो गया।

मैंने अपने पहले के व्याख्यानों और लेखों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अब 'तानाशाही' का जमाना गया। अब भविष्य में माओ जेदांग, पार्क चुंग ही या जोसेफ स्टालिन जैसे नेताओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हर देश में शिक्षित मध्य वर्ग की बढ़ती संख्या अब शासन में अपनी आवाज बुलंद कर रही है और अब वह नीति निर्माण का हिस्सा बनना चाहती है न कि पहले की भांति नीतियों के सुफल या कुफल भोगना। आज ज्यादा से ज्यादा समाज और सरकारें सामाजिक संविदा के सिद्धांत को स्वीकार कर रही हैं। इसे हमने अभी हाल में ही मध्य और उत्तर अफ्रीका के देशों में शुरू हुई अरब क्रांति के रूप में देखा है और अब इसका छोटे स्तर पर प्रभाव हम कुछ अन्य देशों जैसे मलेशिया और सिंगापुर में भी देख रहे हैं, जहाँ स्वतंत्रता के बाद से ही शासन कर रही पार्टियों के विरोध में विपक्षी दल आवाज उठा रहे हैं और अपनी भूमिका को विस्तारित कर रहे हैं। पिछले वर्ष दिल्ली विधान सभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत ने इस बात को और पुख्ता किया है कि अब अधिक खुले और पारदर्शी शासन की मांग बढ़ रही है। यहाँ तक कि अब चीन में भी, जहाँ एक दलीय शासन है, नये नेतृत्व ने लोगों की नजरों में अपनी छवि को सुधारने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने शानदार सरकारी भोजों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है और यहाँ तक कि कार्यालयीन व्यंजनों की संख्या तक भी निश्चित कर दी है: चार कोर्स मील और सूप। उन्होंने हमारे गृह से विलुप्त हो रही शार्क फिन को भी भोजन में शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आम जनता के सरोकारों पर इस प्रकार ध्यान दिया जाना यह सिद्ध करता है कि वह अपने अस्तित्व के लिए जनता को साथ लेकर चलना चाहती है।

अंतिम मानदंड है– बहुपक्षवाद। हमारी आज की सभी गंभीर समस्याएँ स्थानांतरीय (ट्रांसलेशनल) स्वरूप की हैं फिर चाहे वह महामारी हो या जलवायु परिवर्तन; अथवा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद हो या वित्तीय संकट। इसने क्षेत्रीय तथा वैश्विक दोनों स्तरों पर बहुपक्षीय पहलों की भूमिका पर बल देते हुए इस विचारधारा को मजबूत किया है कि स्थानांतरीय समस्याओं के लिए स्थानांतरीय सहयोग की आवश्यकता होती है। इन सभी संगठनों की बैठकों में जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात उभरकर आई है, वह यह है कि अब सिविल सर्वेंट्स और नेताओं को एक–दूसरे से मिलने, चर्चा करने और समझौते करने के ज्यादा अवसर मिलते हैं, जिससे नीति निर्माताओं के बीच विश्वास अधिक मजबूत हुआ है। उदाहरण के लिए आसियान, जो कि यूरोपीय संघ के बाद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सफल क्षेत्रीय संगठन है, ने कई अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं जैसे ईस्ट एशिया समिट, आसियान क्षेत्रीय फोरम आसियान+3, व आसियान+8 समूह बनाए हैं, जो कि एशिया प्रशांत के देशों को हर वर्ष मिलने के अवसर प्रदान करते हैं। इसमें यू एस, चीन और भारत जैसी बड़ी शक्तियाँ शामिल हैं।

यह सभी अभूतपूर्व घटनाएं हैं जो बहुत तेजी से घट रही हैं। इससे पहले मानव इतिहास में कभी भी न तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से निजात मिली है और न ही इतने लोग शिक्षित हुए हैं और न ही इतने ज्यादा लोगों ने संसार का भ्रमण किया है। इन स्थितियों ने कारोबारियों और नीति निर्माताओं को तमाम नए अवसर दिए हैं। अपनी पुस्तक 'दि ग्रेट कनवर्जेंस' में मैंने भारत में तेजी से बढ़ रहे और सफल आउटसोर्सिंग बिजनेस के जनक इनफोसिस के श्री नारायणमूर्ति तथा सन माइक्रो सिस्टम्स के श्री विनोद खोसला जी का जिक्र किया है। इसके साथ ही मैंने भारत की वास्तविक क्षमताओं और उपलब्धियों के बीच अंतर के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। यह बात आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप भारतीय कंपनियों के नवाचार और उनकी गुणवत्ता की देश के आर्थिक निष्पादन से तुलना नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पूरे विश्व से आए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा उद्यमियों के बीच एक–दूसरे से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रहती है, किन्तु वहाँ भारतीय लगातार शीर्ष स्थान हासिल कर रहे हैं। अमेरिका में बसे भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय वहाँ बसे किसी अन्य देश के लोगों से ज्यादा है;

2010 में भारतीयों की आय 37,931 यू एस डॉलर थी जबकि अमेरिकियों की औसत आय मात्र 26,708 यू एस डॉलर ही थी। यदि भारत में बसे भारतीय, अमेरिका में बसे भारतीयों का मात्र आधा जी डी पी आय स्तर ही हासिल कर लें तो भारत का जी डी पी 1.85 ट्रिलियन यू एस डॉलर की बजाए 24.65 ट्रिलियन यू एस डॉलर हो जाएगा। इटली जहाँ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की मात्र 5 प्रतिशत ही है, का जी डी पी भारत से ज्यादा है।

इस ग्रेट कनवर्जेंस में भारत की पूर्ण सहभागिता नीति निर्माताओं और कारोबारी समुदाय के बीच बेहतर ताल–मेल से ही सुनिश्चित हो सकेगी। भारत के एक प्रमुख बौद्धिक विचारक श्री प्रताप भानु मेहता ने बड़ी बेबाकी से कहा है कि 'चीन में समाज तो बंद है किन्तु दिमाग खुले हैं जबकि भारत में समाज खुला है किन्तु दिमाग बंद है।' चीन में एक दलीय शासन पद्धति है और अभिव्यक्ति की सीमित आजादी होने के बावजूद उसका नेतृत्व व्यावहारिक और खुले दिमाग का है, जिसे डेंग जिआओपिंग ने एक कहावत के जरिए अच्छी तरह से स्पष्ट किया है – 'जब तक बिल्ली चूहे का शिकार कर रही है, तब तक यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि बिल्ली काली है या सफेद है।' इसके विपरीत भारत की छवि एक बड़े और सफल प्रजातंत्र तथा अमर्त्यसेन के 'आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन' जैसी बौद्धिक चर्चाओं वाले देश की है। इसके बावजूद भारत अभी भी कुछ अप्रचलित और गलत आर्थिक अवधारणाओं से चिपका हुआ है, जिसने इसे दुर्भाग्यवश विश्व की रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था बना दिया है। तथाकथित प्राचीन ज्ञान भी भारत के विकास के अवरोधों को दूर नहीं कर सका है।

भारत के बारे में मुझे सिर्फ यही चिन्ता है कि कहीं ऐसा न हो कि यह इस ग्रेट कनवर्जेंस से उभरे स्वर्णिम अवसरों का लाभ उठाने से छूट न जाए। वर्तमान में भारत की जनसंख्या काफी युवा है और इतनी बड़ी युवाश्रम शक्ति के होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था उसका लाभ नहीं ले पा रही है और लड़खड़ा रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कामगार जनसंख्या कुल जनसंख्या का 63.4 प्रतिशत है। चीन युवा जनसंख्या की लाभप्रद स्थिति से बाहर हो चुका है जिसमें भारत अब प्रवेश कर रहा है। इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत चीनी निवेशकों को भी आकर्षित कर सकता है। किन्तु

विदेशी निवेशक विनिर्माण गतिविधियों के लिए बांग्लादेश तथा वियतनाम को वरीयता दे रहे हैं। फिलीपींस, जिसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 8 प्रतिशत से भी कम है, के बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग खंड में, जो कि तेजी से बढ़ता और आकर्षक क्षेत्र है, में भारत से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं।

भारत इस ग्रेट कनवर्जेंस से उपजे अवसरों का लाभ तभी उठा सकता है जब वह अपनी उस संपदाओं का लाभ उठाए जिनका अभी तक अपव्यय हो रहा है। भारत की पहली संपदा है– इसका बेहद सफल और विस्तारित विदेशों में बसा भारतवंशी (इंडियन डायस्पोरा) वर्ग। विदेशों में बसे भारतवंशियों की कुल सम्मिलित संपदा 1 ट्रिलियन यू एस डॉलर या भारत के कुल जी डी पी की आधी है। भारत विदेशी प्रेषणों का भी सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है तथा 2013 के दौरान भारत को 70 बिलियन यू एस डॉलर की विदेशी मुद्रा संप्रेषणों के जरिए प्राप्त हुई। विदेशों में भारतवंशी केवल विदेशी रेमिटेंस के लिहाज से ही महत्त्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि वे भारत के लिए अन्य दृष्टि से भी अकूत पूँजी हैं। अमेरिका में भारतीयों ने 18 प्रतिशत से अधिक नए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग उद्यम शुरू किए हैं जबकि अमेरिका की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत है। सिलिकॉन वैली की 14 प्रतिशत से अधिक कंपनियों की स्थापना भारतीयों द्वारा की गई है। अमेरिका के कई शीर्ष बिजनेस स्कूल्स में भारतीय शीर्ष पदों पर रह चुके हैं–इनमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स में नितिन नोहरिया, शिकागो यूनिवर्सिटी में सुनील कुमार तथा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में सौमित्र दत्ता प्रमुख हैं। किसी अमेरिकी बिजनेस स्कूल का नेतृत्व करने वाले दीपक सी. जैन शायद पहले भारतीय थे जिन्होंने 2011 से 2013 तक इनसीड का डीन के रूप में नेतृत्व किया। इससे पहले वे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग्स स्कूल में 13 वर्ष तक डीन रहे।

भारत को चाहिए कि वह इस प्रकार की बेहतरीन प्रतिभा से संपन्न और सफल उद्यमियों को भारत को वापस आने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि उन्हें अमेरिका की बेहतरीन आधुनिक सुविधाओं और उदार वेंचर कैपिटल फंडिंग व्यवस्था का व्यापक अनुभव है। आप इससे सहमत होंगें कि कारोबार को बढ़ावा देने वाले राजनैतिक और विधिक संस्थानों की स्थापना करना कोई आसान काम नहीं है। आप सबको

मालूम ही होगा कि भारत लगातार विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पीटिवनेस रैंकिंग में अपनी रैंकिंग खोता रहा है। 2013 में 148 देशों की इस रैंकिंग में भारत पिछले वर्ष के 59 वें स्थान से खिसककर 60वें स्थान पर आ गया है। हालांकि भारत की स्थिति अपने आकार के अनुसार कुछ सूचकांकों जैसे जी डी पी (क्रय शक्ति समानता के आधार पर) तथा घरेलू बाजार के मामले में अच्छी रही है किन्तु नीतिगत मामलों में इसकी रैंकिंग काफी खराब रही है। उदाहरण के लिए कराधान दरों व व्यापार कर आदि के मामले में भारत 128वें स्थान पर रहा। भारतीयों ने यह काफी पहले सिद्ध कर दिया है कि विदेशों में वे काफी प्रतिस्पर्धी हैं इसलिए अब उन्हें उनके अपने देश में विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

कुछ उद्योग क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की शक्ति को हम परख चुके हैं। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन बिजनेस में अपनी शुरूआत के मात्र 5 साल के अंदर माइक्रोमैक्स कंपनी भारत के बाजार में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और लगातार स्मार्टफोन के शीर्ष ब्रांड सैमसंग का बाजार ले रही है। माइक्रोमैक्स का बाजार अन्य दक्षिण एशियाई देशों तथा रूस तक पहुँच चुका है। इसी प्रकार एअरटेल भारत की नंबर एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और इसने वोडाफोन जैसी दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनी को पछाड़ दिया है। समान स्तर पर देशी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा भारत जैसे मूल्य संवेदी देश में न केवल ग्राहकों के लिए बल्कि अन्य कारोबारों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि अंतत: यह परिचालन लागत को कम करती है।

दूसरी सबसे बड़ी संपदा जो भारत के पास है, वह है– अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में इसकी प्रतिष्ठा। चीन के विपरीत, जिसके उत्थान को पश्चिम शक की निगाह से देखता रहा है, भारत के पूरे विश्व के साथ अच्छे संबंध ही रहे हैं।

वास्तव में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क गेन हाय, जापान के सम्राट अकिहितो तथा प्रधानमंत्री शिनाज ऐब की हालिया भारत यात्राओं ने यह सिद्ध किया है कि चीन की राजनैतिक चुनौतियाँ भारत के लिए नए अवसरों के रूप में उभरी हैं जिनका उपयोग भारत अपने सहभागियों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए कर सकता है।

तीसरी सबसे बड़ी संपदा जो भारत के पास है, वह है–यहाँ के अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की योग्यता, जो सिंगापुर को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं है। भारत सरकार के पास विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री हैं इनमें स्वयं प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, रिज़र्व बैंक के मौजूदा गवर्नर डॉ. रघुराम राजन, जिन्होंने 2008 के वित्तीय संकट की पहले ही घोषणा कर दी थी, यह बात और कि उस पर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था। डॉ. रघुराम राजन के पूर्ववर्ती भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार डॉ. कौशिक बसु, जो अब विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। यह सूची काफी लंबी हो सकती है। फिर भी भारतीय नीति निर्माता राजनैतिक मकड़जाल में फँसे हैं तथा ऐसी नीतियाँ नहीं बना रहे हैं जो विकास का मार्ग प्रशस्त करें। इकोनॉमिक टाइम्स ने 2012 में अपने एक लेख में प्रकाशित किया था कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इतनी नकदी है कि वे 40 हजार किमी. के 6 लाइनों वाले हाइवे को बनाने में आने वाले खर्च के बराबर की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की फंडिंग कर सकती हैं। इसके बावजूद उसी वर्ष भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निजी निवेश में 52 प्रतिशत की गिरावट आई जिससे बड़ी परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब सहित लागत भी काफी बढ़ गई। नीतिगत प्रोत्साहनों के अभाव में निवेशकों ने परियोजनाओं में रुचि नहीं दिखाई।

इस पूरे विश्लेषण का सार यह है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अकूत क्षमताएँ और संभाव्यताएँ हैं और भारत यदि अपनी क्षमताओं के बराबर प्रदर्शन करे तो वह शीर्ष देश बन सकता है। मैकिंजी ने अभी हाल ही में रि–इमैजिनिंग इंडिया[2] नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में मेरा भी एक लेख है जिसमें मैंने लिखा है कि यदि हर भारतीय की औसत आय अमेरिका में बसे भारतीयों की औसत आय की आधी भी हो जाए तो भारत का जी डी पी वर्तमान 2 ट्रिलियन यू एस डॉलर के बजाय 25 ट्रिलियन यू एस डॉलर हो जाएगा।

इन संभावनाओं तथा पिछले तीन दशकों में ग्रेट ग्लोबल कनवर्जेंस में सहभागी बने कई विकासशील देशों में हुई तरक्की को देखते हुए भारत की जनता तथा नीति निर्माताओं को आपसी सहमति से कुछ

[2] री–इमैजिनिंग इंडिया, मैककिन्सी एंड कंपनी, http://www.mckinsey.com/features/reimaginingindiabook.

ऐसा रोडमैप बनाना चाहिए ताकि भारत की विकास दर 7 से 9 प्रतिशत वार्षिक बनी रहे। भारत पिछले कुछ वर्षों में यह विकास दर हासिल भी कर चुका है। सिंगापुर के संस्थापकों श्री ली कुआन यू तथा श्री गो केंग स्वी के साथ काम करते हुए जो सबसे बड़ा सबक मैंने सीखा है वह है– सफलता के लिए आपको पहले स्वयं पर विश्वास करना होगा और फिर दूसरों से सीखने की क्षमता विकसित करनी होगी। कई भारतीयों ने यह प्रदर्शित किया है कि वे दोनों कर सकते हैं। अत: अब भारत के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है जब उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए था भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के तीव्र पथ पर डालना चाहिए। अब भारत की ही बारी है।

प्रो. किशोर महबुबानी सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हुए भी आम मुद्दों पर बड़े विस्तृत रूप से लिखते रहे हैं। आपने सिंगापुर विदेश सेवा के लिए 33 वर्षों (1971-94) तक कार्य किया है। अपने कार्यकाल के दौरान आपकी पोस्टिंग कम्बोडिया (1973-74), मलेशिया, वाशिंग्टन डी. सी. तथा न्यूयार्क में रही। आपको संयुक्त राष्ट्र में दो बार कार्य करने का अवसर मिला – पहली बार जनवरी 2001 सिंगापुर के राजदूत के रूप में तथा दूसरी बार मई 2002 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में। आप विदेश मंत्रालय में वर्ष 1993 से 1998 तक स्थायी सचिव रहे। वर्तमान में आप प्रैक्टिस ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी, ली क्युऑन यू स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी (एल के वाई एस पी पी), नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर के डीन तथा प्रोफेसर हैं। आपके कई लेख/पुस्तकें विश्व स्तर पर प्रकाशित हुई हैं। आपकी हालिया पुस्तक ''दि ग्रेट कन्वरजेन्सः एशिया, दि वेस्ट, एंड दि लॉजिक ऑफ़ वन वर्ल्ड'' है जिसे फायनेंशियल टाइम्स द्वारा वर्ष 2013 की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में चुना गया है।

प्रो. महबुबानी को 1967 में प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप से नवाजा जा चुका है। आपने वर्ष 1971 में सिंगापुर यूनिवर्सिटी से दर्शनशास्त्र ऑनर्स तथा 1976 में डलहौजी यूनिवर्सिटी, कनाडा से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री व 1995 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। आप वर्ष 1991-92 के दौरान हॉवार्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स में अध्येता के पद पर भी एक वर्ष तक कार्य कर चुके हैं।

अब तक प्रकाशित किए गए वार्षिक व्याख्यानों की सूची

क्रमांक	दिनांक	वक्ता	अध्यक्षता	विषय
1)	03.03.1986	**डॉ. दीपक नय्यर** प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू, नई दिल्ली	**डॉ. सी. रंगराजन** उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार – विकासशील देशों के लिए निहितार्थ
2)	17.03.1987	**डॉ. पार्थ दासगुप्त** प्रो. ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यू.के.	**डॉ. सी. रंगराजन** उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	अर्थव्यवस्थाओं का संसाधन आधार
3)	04.02.1988	**डॉ. आबिद हुसैन** सदस्य योजना आयोग	**डॉ. वी.जी. राजाध्यक्ष** योजना आयोग के पूर्व सदस्य	भारतीय आयोजना में विदेश व्यापार नीति
4)	02.03.1989	**श्री एम. नरसिंहम** उपाध्यक्ष एडमिनिसट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद	**श्री डी.एन. घोष** अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक	वित्तीय बाज़ारों का भूमंडलीकरण और भारत
5)	05.03.1990	**श्री सिडनी डेल** वरिष्ठ अध्येता, यूनाइटेड नेशन्स इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च	**श्री आर.एन. मल्होत्रा** गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	1990 के दशक के कार्यों के लिए विश्व बैंक में सुधार करना
6)	15.03.1991	**प्रो. प्रणव वर्धन** प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया, बर्कले	**डॉ. किरीट पारिख** निदेशक आई जी आई डी आर	सरकार और गतिशील तुलनात्मक लाभ
7)	05.03.1992	**डॉ. (सुश्री) इशर जज अहलूवालिया** रिसर्च प्रोफेसर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली	**डॉ. वी. कृष्णमूर्ति** सदस्य योजना आयोग	भारत की व्यापार नीति और औद्योगीकरण
8)	04.01.1993	**लॉर्ड मेघनाद देसाई** प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यू.के.	**डॉ. एस. एस. तारापोर** उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	पूँजीवाद, समाजवाद और भारतीय अर्थव्यवस्था

क्रमांक	दिनांक	वक्ता	अध्यक्षता	विषय
9)	21.03.1994	**डॉ. विजय जोशी** अध्येता मेर्टन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड	**प्रो. कौशिक बसु** दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स	समष्टिगत आर्थिक नीति और भारत में आर्थिक सुधार
10)	27.03.1995	**डॉ. स्टेनले फिशर** प्रथम उप प्रबंध निदेशक आई एम एफ, यू एस ए	**डॉ. सी. रंगराजन** गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	आर्थिक गरीब और सुधार
11)	06.03.1996	**श्री रजत गुप्ता** प्रबंध निदेशक मैककिन्जी एंड कं. आईएनसी, यू एस ए	**डॉ. फ्रेडी ए. मेहता** अध्यक्ष फोर्ब्स ग्रुप	उत्पादकता के नए शिखर
12)	04.03.1997	**डॉ. पेड्रो आस्पे** पूर्व वित्त मंत्री, मैक्सिको	**डॉ. वाई.वी. रेड्डी** उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	निजीकरण और भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ – मेक्सिको के अनुभव
13)	30.03.1998	**श्री चार्ल्स एच. डाल्लारा** प्रबंध निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल फायनेंस, वाशिंग्टन डी.सी.	**श्री एस.एस. तारापोर** पूर्व उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	एशियाई मुद्रा संकट के बाद उभरते हुए बाजारों और भारत का परिदृश्य
14)	10.03.1999	**डॉ. सी. फ्रेड बर्गस्टन** निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वाशिंग्टन डी.सी.	**श्री ए.वी. गणेशन** पूर्व वाणिज्य सचिव, भारत सरकार	भारत और वैश्विक व्यापार प्रणाली
15)	29.03.2000	**डॉ. इसुके सकाकीबारा** प्रोफेसर केइयो यूनिवर्सिटी, जापान	**डॉ. बिमल जलान** गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	21वीं शताब्दी में एशिया – भारत और जापान की भूमिका
16)	22.03.2001	**प्रोफेसर निकोलस स्टर्न** मुख्य अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष, विश्व बैंक, वाशिंग्टन डी.सी.	**डॉ. शंकर आचार्य** मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	भारत में निवेश, विकास तथा गरीबी में कमी के लिए वातावरण बनाना

क्रमांक	दिनांक	वक्ता	अध्यक्षता	विषय
17)	22.04.2002	**डॉ. पर पिंस्ट्रुप-एंडरसन** महानिदेशक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाशिंग्टन डी.सी.	**डॉ. एम.एस. गिल** पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार	वैश्वीकरण में भारतीय कृषि
18)	05.08.2003	**जेम्स बी. बोल्जर, ओ एन ज़ेड** पूर्व प्रधान मंत्री, न्यूजीलैंड अध्यक्ष, वर्ल्ड एग्रीकल्चरल फोरम	**श्री जगदीश कपूर** अध्यक्ष कृषि वित्त निगम	कृषि में अंतरराष्ट्रीय व्यापार: उभरते परिदृश्य
19)	10.03.2004	**डॉ. एडुआर्डो अनिनात** पूर्व उप प्रबंध निदेशक इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड एवं पूर्व वित्त मंत्री, चिले	**डॉ. विजय केलकर** सलाहकार, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय	विकासशील देशों के परिदृश्य में व्यापार और वित्तीय क्षेत्र में भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ
20)	10.03.2005	**श्री रूबिंस रिकोपेरो** पूर्व महासचिव, अंकटाड	**श्री तरूण दास** चीफ मेंटॅर, सी आई आई	व्यापार और विकास: विकासशील देशों के लिए चुनौतियाँ
21)	02.05.2006	**सर सुमा चक्रबर्ती** स्थायी सचिव डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डेवेलपमेंट, यू. के.	**श्रीमती श्यामला गोपीनाथ** उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	व्यापार और विकास में राष्ट्र की भूमिका
22)	20.04.2007	**डॉ. डेविड ह्यूम** प्रो. ऑफ़ डेवेलपमेंट स्टडीज, आई डी पी एम, यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैनचेस्टर, यू. के.	**डॉ. राकेश मोहन** उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	समावेशी वैश्वीकरण: चिरकालिक गरीबी को दूर करना
23)	18.03.2008	**श्री केमल दर्विश** प्रशासक यूनाइटेड नेशन्स डेवेलपमेंट प्रोग्राम (यू एन डी पी)	**डॉ. अरविन्द विरमानी** मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	विश्व अर्थव्यवस्था की नई संरचना का परिदृश्य
24)	13.03.2009	**श्री जस्टीन यिफु लिन** मुख्य अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्व बैंक	**डॉ. दिलीप एम. नाचणे** निदेशक इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेवेलपमेंट रिसर्च, मुम्बई	कींस के अर्थशास्त्र से परे–विकास के प्रोत्साहन

क्रमांक	दिनांक	वक्ता	अध्यक्षता	विषय
25)	18.03.2010	**डॉ. सुपाचई पैनिचपाकड़ी** अंकटाड के महासचिव	**डॉ. सुबीर गोकर्ण** उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	आर्थिक अभिशासन का पुनर्निर्माण: संपोषी वृद्धि तथा विकास का एजेंडा
26)	27.07.2011	**प्रो. यु यांगडिंग** अध्यक्ष, चाइना सोसायटी ऑफ़ वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट	**डॉ. वाई.वी. रेड्डी** उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	चीन की अर्थव्यवस्था का पुनर्संतुलन
27)	21.11.2012	**प्रो. जगदीश भगवती** प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ एंड इंटरनेशनल अफेयर्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी	**डॉ. सुबीर गोकर्ण** उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	विश्व व्यापार प्रणाली में परिवर्तन: भारत के विकल्प
28)	14.03.2013	**प्रो. प्रणब बर्धन** प्रोफेसर ऑफ़ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलीफोर्निया, बर्कले	**डॉ. उर्जित आर. पटेल** उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	व्यापार और विकास का सिद्धांत : भारतीय परिप्रेक्ष्य
29)	14.02.2014	**प्रो. किशोर महबुबानी** डीन, ली क्युऑन यू स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर	**डॉ. दिलीप एम. नाचणे** सदस्य, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद	बदलते वैश्विक समीकरण: क्या भारत इनका लाभ उठा पाएगा?

''निर्धारित लक्ष्य के साथ विदेश उन्मुख कंपनियों के अंतरराष्ट्रीयकरण प्रयासों में अभिवृद्धि करने के लिए उन्हें उद्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रेणी प्रदान करके उनके साथ वाणिज्यिक रूप में व्यवहार्य संबंध विकसित करना है।''

– एक्ज़िम बैंक की दृष्टि

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

21वीं मंजिल, केन्द्र-1 भवन, विश्व व्यापार केन्द्र,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
दूरभाष: + 91 22 2217 2600 • फैक्स: + 91 22 2218 2572
ईमेल: ccg@eximbankindia.in